

सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमको नींद नहीं आने देते।

- अज्ञात

‘दूर ऑफ ड्यूटी’ प्रस्ताव

सेना ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिस स्तर की भर्ती के लिए जो भी पात्रताएं तय हैं, उनमें कोई ढील नहीं दी जाएगी। यह सावधानी इसलिए जरूरी है कि बड़ी संख्या में और कम अवधि के लिए लोगों का आना सेना की कार्य संस्कृति के लिए समस्या खड़ी कर सकता है।

अनु वर्मा।

सेना की ओर से दिया गया तीन साल सेवा का ‘दूर ऑफ ड्यूटी’ प्रस्ताव जवानी की दहलीज पर कदम रख रही पीढ़ी में जबर्दस्त उत्सुकता और दिलचस्पी जगाएगा। इसे उन युवाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है जो सैन्य सेवाओं का रोमांच तो महसूस करना चाहते हैं, लेकिन अपना जीवन सेना तक ही सीमित नहीं रखना चाहते।

प्रस्ताव यह है कि अर्हता-पात्रता की सीमाओं को पार करने और एक निश्चित प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने के बाद लोग तीन साल तक सेना को अपनी सेवाएं दें, फिर अलग करियर अपना कर नागरिक जीवन में इस अनुभव का लाभ उठाएं। देश में नौकरियों का हाल देखते हुए इस प्रस्ताव की उपयोगिता और बढ़ जाती है।

सैन्य प्रशिक्षण और तीन साल की सैन्य सेवा से युवा ऊर्जा को एक स्पष्ट दिशा मिलेगी सौ अलग। फिजिकल फिटनेस के अलावा देशभक्ति, अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना इन युवाओं को न केवल बेहतर नागरिक बनाएगी बल्कि विभिन्न प्रोफेशनल भूमिकाओं के लिए उनकी पात्रता को भी नई ऊंचाई देगी।

इजराइल जैसे कुछ देशों में न्यूनतम सैन्य प्रशिक्षण को अनिवार्य बनाया गया है, लेकिन अपने यहां इस प्रस्ताव का स्वरूप पूरी तरह ऐच्छिक है। सेना ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिस स्तर की भर्ती के लिए जो भी पात्रताएं तय हैं, उनमें कोई ढील नहीं दी जाएगी। यह सावधानी इसलिए जरूरी है कि बड़ी संख्या में और कम अवधि के लिए लोगों का आना सेना की कार्य संस्कृति के लिए समस्या खड़ी

कर सकता है। इस प्रस्ताव का एक फायदा यह भी बताया जा रहा है कि लंबी अवधि में इससे सैनिकों के वेतन, पेंशन और ग्रैज्युटी आदि पर आने वाले खर्च में कमी आएगी।

सवाल सेना के मनोबल और कौशल का हो तो खर्च को किसी बदलाव का महत्व नापने की कसौटी नहीं बनाया जा सकता, लेकिन अगर सारी जरूरतें पूरी करने के बाद भी इससे खर्च कुछ कम होता हो तो इसको आजमाने में कोई हर्ज नहीं है। यह जरूर है कि उच्च तकनीकी और ऑटोमेशन के इस युग में दुनिया का जोर सैन्य बलों की संख्या कम करके उनका तकनीकी कौशल और मैदानी दक्षता बढ़ाने पर है। उनका लक्ष्य ऐसे स्मार्ट सैनिक विकसित करने का है, जो कई स्रोतों से आ रही सूचनाओं का उपयोग

करते हुए अत्याधुनिक हथियारों और उपकरणों के बल पर अपने काम को बेहतर ढंग से अंजाम दे सकें।

ऐसे में कुछ लोगों के मन में सवाल उठ सकता है कि भारतीय सेना तीन-तीन साल के लिए युवाओं को शामिल करके कौशल से ज्यादा संख्या को महत्व देने की गलती तो नहीं कर रही। लेकिन याद रहे, सेना ने ‘दूर ऑफ ड्यूटी’ का प्रस्ताव स्थायी ऑफिसरों और सैनिकों की जगह लेने के लिए नहीं दिया है। उसके पास कई तरह के फौजियों के लिए कई तरह के काम हैं।

मौजूदा प्रस्ताव के उद्देश्य और उसकी सीमाओं को ध्यान में रखें तो यह सेना के साथ-साथ नागरिक समाज के लिए भी काफी उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

अस्तित्व

अशोक वोहरा।

किसी भी बच्चे का अपना एक व्यक्तिगत अस्तित्व है और जल्द ही वह इसे अपने एक स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में विकसित कर

लेता है। हम वस्तुओं के अधिकारी बन सकते हैं पर मानवों के नहीं। किसी भी मां का अपने बच्चे की मदद करना और उसका मार्गदर्शन करना, उसके अंदर उस बच्चे पर अधिकार की भावना विकसित कर देता है। इस भावना के कारण आगे चलकर कई समस्याएं शुरू हो जाती हैं। मुख्य रूप से तब जब बच्चा बड़ा होकर अपने जीवन की बातें अपनी मां के बजाय अपने जीवनसाथी से साझा करना शुरू कर देता है। पतंग को नचाने के हमारे काम को देखने में केवल तभी आनंद आयेगा जब यह आसमान में अपने जीत का दावा कर देगा।

धर्म-दर्शन



संपादकीय

बजट के भीतर-बाहर

ग्रामीण क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, बागवानी, फल एवं सब्जी और मुर्गी पालन करने वाले किसानों की कमर संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से टूट गई है। जो घोषणाएं वित्त मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए की हैं इनमें से ज्यादातर वर्ष 2020-21 के बजटीय भाषण में वे पहले ही कर चुकी हैं। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के एक सर्वे के अनुसार देश में 67 प्रतिशत मजदूरों ने लॉक डाउन के दौरान अपना रोजगार खो दिया। शहरी क्षेत्र में 10 में से 8 मजदूरों के पास रोजगार नहीं था जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 10 में से छह मजदूरों के पास रोजगार नहीं रहा।

वर्ष 2020-21 के बजट में नाबार्ड को 90 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान सीमांत किसानों को लोन देने के लिए किया गया था। कोरोना संक्रमण के बाद 30 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान और किया गया। साथ ही तीन करोड़ सीमांत किसानों के लिए चार लाख करोड़ का फसली ऋण उपलब्ध कराने की बात भी कही गई है। ऐग्रिकल्चर सेंसस के अनुसार देश के 14.50 करोड़ किसानों में से 12 करोड़ 30 लाख सीमांत किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि है। ऐसे में प्रश्न उठता है बाकी 9 करोड़ 30 लाख किसानों का क्या होगा? वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार का 30 लाख 42 हजार करोड़ का बजटीय खर्च है। मतलब यह कि अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए दिया गया पैकेज बजट घोषणाओं से बाहर है या बजटीय घोषणाओं में ही इस पैकेज का समावेश किया गया है, यह केंद्र सरकार को तुरंत ही स्पष्ट करना चाहिए।

यदि सरकार इन 13 करोड़ परिवारों के बैंक अकाउंट में सीधा पैसा भेजती तो निश्चित ही भारतीय बाजार में मांग पैदा होती जिसकी वजह से उद्योगों को सीधा लाभ मिलता।

कोई स्पष्टता नहीं दिखती

राजीव त्यागी।

वित्त जब आती है तो चारों ओर से आती है। कोरोना के संक्रमण से भय और अनिश्चितता का माहौल, बेमौसम बरसात और देश में पहले से व्याप्त आर्थिक मंदी यही साबित कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था को उबारने और देश के नागरिकों को राहत देने के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की। पैकेज में सबसे बड़ा हिस्सा बैंकों से मिलने वाले कर्ज का है। सवाल है कि यदि बाजार में मांग ही नहीं होगी तो लोन लेकर उद्योग अपने उत्पादों की आपूर्ति कहां करेंगे। देश में 6 करोड़ 30 लाख सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग हैं। इस एमएसएमई सेक्टर में 45 लाख उद्योगों को तीन लाख करोड़ रुपये बिना किसी गारंटी के लोन देने की बात कही गई है। क्षेत्र के बाकी बचे उद्योगों के लिए सरकार के पास क्या कार्य योजना है, इस पर कोई स्पष्टता नहीं दिखती।

एमएसएमई सेक्टर में कार्य करने वाले 11 करोड़ कर्मचारियों के हितों को लेकर भी सरकार खामोश है। इन कर्मचारियों को 2-3 माह से वेतन नहीं मिला, जिसके चलते वे भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। इस पैकेज की घोषणा करने से पहले सरकार को यह भी ध्यान रखना चाहिए था कि वर्ष 2019 दिसंबर में एमएसएमई



सेक्टर को दिए गए कुल लोन का 12.6 प्रतिशत यानी 2 लाख 3 हजार करोड़ रुपये एनपीए होने की तरफ बढ़ गया था। पैकेज में उन 13 करोड़ परिवारों के बारे में भी नहीं सोचा गया है जो कोविड-19 के संक्रमण के बाद सबसे ज्यादा परेशानी में हैं। यदि सरकार इन 13 करोड़ परिवारों के बैंक अकाउंट में सीधा पैसा भेजती तो निश्चित ही भारतीय बाजार में मांग पैदा होती जिसकी वजह से उद्योगों को सीधा लाभ मिलता। अर्थव्यवस्था का सीधा सा नियम है कि यदि लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी तो उससे उत्पादों की मांग बढ़ेगी। उद्योगों के लिए मुद्रा की तरलता के साथ-साथ सरकार को इस तरह के राजकोषीय

उपाय करने चाहिए जिनसे देश के नागरिकों की जब में सीधा पैसा जाए। कर्मचारी भविष्य निधि के लिए सरकार ने 2500 करोड़ का प्रावधान किया परंतु उससे पहले ही वह कर्मचारियों के भत्तों पर कैंची चला चुकी है, जिससे क्रय शक्ति का और झंझा ही होगा।

प्रवासी मजदूर और ग्रामीण क्षेत्र भयंकर पीड़ा के दौर से गुजर रहे हैं। सरकार ने घोषणा की है कि राशन कार्ड हो या न हो आठ करोड़ प्रवासी मजदूरों को 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने 3500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। 19 करोड़ परिवारों को अप्रैल माह में 1 किलो दाल दी जानी थी। उपभोक्ता मामले मंत्रालय के अनुसार कुल 15: परिवारों को ही इसका लाभ मिला। अप्रैल में एक लाख 96 हजार टन दाल का वितरण होना था जबकि 30 हजार टन दाल का ही वितरण हो पाया। एक देश एक राशन कार्ड के आधार पर राशन देने की शुरुआत अच्छी है परंतु जिस गति से ये कार्ड बन रहे हैं, वह कछुए की गति से भी बदतर है।

मनरेगा योजना को लेकर भी घोषणाएं की गईं परंतु ये भी वास्तविकता से काफी दूर हैं। देश में 7 करोड़ 60 लाख मनरेगा मजदूर पंजीकृत हैं। मार्च में एक करोड़ 60 लाख मजदूरों को रोजगार मिला, जबकि अप्रैल में मात्र 30 लाख व्यक्तियों को रोजगार हासिल हुआ।

सूडोकू बत्ताल- 5356				*****			
4						1	8
		6	7				2
		8					
8	5						
2		1				7	
						3	5
				5			
1			4	7			
9	6						4

सूडोकू बत्ताल- 5355 का हल

■ प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं।
 ■ प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3x3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें।
 ■ पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते।
 ■ पहेली का केवल एक ही हल है।

अपना ब्लॉग भारी नुकसान हो रहा है

मोहन। मनरेगा योजना के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपना पंजीकरण करा लेता है और उसको रोजगार नहीं मिलता है तो उसको पहले माह कुल दैनिक मजदूरी का चौथाई, अगले माह आधा और तीसरे माह पूरी मजदूरी देने का प्रावधान है, भले उसको काम दिया गया हो या नहीं। मंडियों में किसान रबी की फसल की बिकवाली कर रहा है। उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दाम में अपनी फसल की बिकवाली करनी पड़ रही है जिसकी वजह से उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। पिछले कुछ सालों में लागत मूल्यों में तो बेतहाशा वृद्धि हुई है, परंतु समर्थन मूल्य में उस तरह से बढ़ोतरी नहीं की गई है। सरकारी खरीद में गेहूँ और चावल के कुल उत्पादन का करीब 25 से 30 प्रतिशत ही खरीदा जाता है।

शादी में नागिन की जगह कोरोना डांस की प्रेक्टिस कर रहे हैं...

